

प्रेषक,

वीरेन्द्र पाल सिंह,  
अनुसचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिला सहायक निबन्धक,  
सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-१ देहरादून दिनांक ।। जून, 2009

वषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष लेखानुदान में जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 993/ नियो०/जिला योजना/ 2009-10 दिनांक 14.05.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 लेखानुदान में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजना (सामान्य) हेतु कुल रूपया 101.77 लाख रूपये (रु० एक करोड़ एक लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल निम्नाकिंत शर्तों के तहत सर्व स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय ।

(2) सभी कार्यकर्ता की वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण धनराशि के आहरण पूर्व तत्काल किया जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों को वित्त, नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाय ।

(3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा विस्तीर्ण अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

(4) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी०एम०-१३ पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

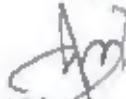
(5) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुरितका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुरितका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण सहित शासन/ महालेखाकार उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय ।

(7) समितियों को अनुदान/राज सहायता/अंशादान दिये जाने से लेखा शीर्षक 2425—सहकारिता—आयोजनागत—107—केंद्रीय समितियों को सहायता, 108—अन्य सहकारी समितियों को सहायता—800—अन्य व्यय (लघु शीर्षक 07,06,21) 4425—सहकारिता पर पूजीगंत परिव्यय—200—अन्य निवेश (लघु शीर्षक 05) के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

- यह आदेश वित्त विभाग के अशासन संख्या—109 (P) / XXVII-4 / 2009 दिनांक 10.06.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

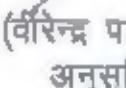
  
(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
अनुसंधिव।

संख्या—/ (1) / XIV-1 / 2009, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री सहकारिता, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलाधुक्त गढ़वाल, / कमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. समरत जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग—4 / नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एनोआईसी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
अनुसंधिव।

प्रासानदेश संख्या 438 / खी-१ / 2009. दिनांक ११ जून 2009 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु उनकृतण समितियों से अनुमोदित जिला सहायक निवड़कों द्वारा बुट्ट के सापेक्ष जनपदों को चौकाति प्रदान करने हेतु लेखाशीर्षकवार घनराशियों का आदंतन का विवरण।

विद्युत विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य लोकोन्नति है। यह योजना विद्युत विभाग के अधिकारी पर जल्दी प्रयोग के लिए तैयार की गई है।

三

三